Pursuant to the above directive, the MMTC has been making its purchases on an equitable basis from all the shippers and mine owners/exporters. From mine owners, who were not exporters, the policy of the Corporation has been to make purchases freely on all sectors where there are no movement or sales difficulties. On such sectors where the rail capacity and/or sales possibilities are limited, the Corporation had earlier followed a policy of making purchases on the basis of acreage held under lease by the mine owners or on the basis of acreage and royalty. Recently purchases are being made on the basis of actual performance in a basic period.

Export of Cow-Boy Shoes to U.S.A.

3489. SHRI CHENGALRAYA NAIDU :
SHRI N. R. LASKAR :
SHRI R. BARUA :

Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India has signed an agreement with U. S. A. for the supply of cow-boy shoes worth Rs. 3 crores to that country ;

(b) if so, the main points of the agreement ;

(c) whether the machines for the manufacture of cow-boy shoes were imported from U.S.A. ; and

(d) if so, the total expenditure involved ;

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) The State Trading Corporation has signed contracts with an U. S. firm for export of cow-boy uppers valued at Rs. 2.91 crores.

(b) These are usual export contracts and the delivery period extends upto the end of December, 1970.

(c) and (d). The machines have been provided by the buyers and the expenditure incurred by the S. T. C. on freight is approximately Rs. 20,000 only.

Import of Foreign Car for Use of Orissa Chief Minister

3490. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of FOREIGN TRADE AND SUPPLY be pleased to state :

(a) whether the present Chief Minister of Orissa had been allowed to import a foreign car recently ;

(b) if so, the value thereof ;

(c) the category under which the import of car from foreign country was allowed to him ; and

(d) the details thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI CHOWDHARY RAM SEWAK) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर द्वारा विमान के सूक्ष्म उपसाधनों का निर्माण

3491. श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ग० च० दीक्षित :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलोर ने विमानों के सूक्ष्म उपसाधनों के निर्माण के लिए एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सूक्ष्म उपसाधन कारखाना स्थापित करने के लिए कौन से राज्य सरकार के विचाराधीन है और उन प्रत्येक राज्यों ने इस उद्देश्य के लिए क्या-क्या रियायतें और सुविधाएं देने का प्रस्ताव किया है ; और

(ग) क्या उक्त कारखाने के लिए स्थान का चुनाव अन्तिम रूप से कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) विमानों के अवयवों के बनाने के लिए हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रस्तावित कारखाने को स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश,

बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित स्थलों के सम्बन्ध में विचार किया गया :-

(1) आंध्र प्रदेश	हैदराबाद
(2) बिहार	आदित्यपुर
(3) हरियाणा	फरीदाबाद
	पंचकुला (चंडीगढ़)
(4) मध्य प्रदेश	भोपाल
(5) राजस्थान	उदयपुर
(6) तमिलनाडु	अम्बतुर
	तिरुचिरापल्ली
(7) उत्तर प्रदेश	लखनऊ
	गाजियाबाद
	देहरादून

राज्य सरकारों को ऐसे स्थलों के विषय में जिन्हें कि वे इस काम के लिए दे सकते थे, और वहां प्राप्त सुविधाओं के विषय में, विस्तृत जानकारी देने के लिए कहा गया था, महाराष्ट्र, से कोई उत्तर नहीं मिला। बिहार, हरियाणा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने कारखाने के लिए मुफ्त भूमि देने की पेशकश की। हैदराबाद में एक जगह लगभग 20 लाख रुपये की कीमत पर और अम्बतूर में एक जगह लगभग 45 से 60 लाख रुपये की कीमत पर देने की बात कही गई थी. बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इसकी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप में या आंशिक रूप में पूरा करने के लिए सहायतायुक्त औद्योगिक आवास की व्यवस्था करने की पेशकश की।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सीनियर स्टाफ के लिए आवास की व्यवस्था करने का काम भी अपने हाथ में लेने की बात कही। अधिकतर राज्य सरकारों ने उस स्थल पर बिजली और पानी की व्यवस्था करने की पेशकश की थी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों ने सहायता प्राप्त पर्याप्त तकनीकी प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने की बात की। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन वर्ष तक बिक्री-कर न लगाने की पेशकश की। लखनऊ के सम्बन्ध में तो राज्य सरकार ने वहां तक कहा कि वे अस्थाई रूप से उस कारखाने को किराये पर दे सकेंगे जो कि उन्होंने राजकीय सूक्ष्म यंत्र कारखाना, लखनऊ के प्रसार के लिए बनाया हुआ है। इस कारखाने में भंडार, प्रारम्भिक संक्रिया और प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त जगह है।

(ग) कारखाने के लिए लखनऊ के पास जो जगह उत्तर प्रदेश सरकार ने देने की पेशकश की थी, वह सबसे उत्तम समझी गई और तदनुसार सरकार ने उस जगह पर वह कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया है।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के निकट सहायक उद्योगों का विकास

3492. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के निकट सहायक उद्योगों का विकास करने और इस काम को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में सरकार की सामान्य नीति क्या है ;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के निकट सहायक उद्योगों के विकास का कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) रक्षा संगठनों के निकट सहायक उद्योगों का विकास संगठन के गुण रूप तथा किसी उत्पादन की सप्लाई करने के लिए आवश्यकता समेत कि जो ऐसे सहायक उद्योग कर सकें विभिन्न पैरामीटरों द्वारा योग्यीकृत है। इसलिये इस संबंध में कोई व्यापक नीति नहीं है। जहां भी यूनिटें स्थापित की गई हैं, उन्हें प्रोत्साहन दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।